	बैंक ऑफ़ इंडिया प्रधान कार्यालय	बीयू-ग्रामीण
शाखा परिपत्र सं.: 116/ 241	विषय : ग्रामीण/2022-23/	
उप-विषय : सामान्य		
संदर्भ : एचओ/ग्रामीण/वाईजेजे/23	दिनांक 03.01.2023	

**समस्त शाखाओं/कार्यालयों के लिए परिपत्र**

**स्टार सखी योजना (एसएसएस)**

**- स्वयं सहायता समूहों की एकल महिला सदस्य  
के वित्तपोषण हेतु योजना**

=====

**1. परिचय :**

भारत की विकास गाथा में प्रमुख जनसांख्यिकीय कारक अर्थात् महिलाएँ पीछे छूट गई हैं। सामाजिक मानदंडों में सुधार के बावजूद भारत के विकास में महिलाओं का आर्थिक समावेश और विकास कम रहा है। श्रम रूझान, तकनीकी विघटन और बाध्यकारी सामाजिक प्रतिबंधों के चलते, काफी हद तक, श्रम शक्ति में महिलाओं की सहभागिता अवरूद्ध सी है और आगे भी इसमें कमी होने की आशंका है। भारत में महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक भूमिका को तवज्जो नहीं मिली है। अधिकतर महिलाएँ बिन-वेतन की देखभाल करने वाली, घर-परिवार की प्रबंधक या घर-परिवार की किसी अन्य भूमिका निभाने वाली के रूप में कार्य करती हैं, घर के बाहर तो कोई छिट-पुट कार्य ही करती हैं। ऐसे समय में, जबकि महिलाएँ पहले की तुलना में अधिक शिक्षित हैं और उनके लिए बेहतर स्वास्थ्य देखभाल उपलब्ध हैं, तब भी वे वैतनिक रोजगार के लिए संरचनात्मक, सामाजिक और आर्थिक प्रतिबंधों का सामना करती हैं। ये सब चीजें महिलाओं की व्यक्तिगत आर्थिक उन्नति को सीमित करती हैं और भारत की सामाजिक और आर्थिक प्रगति को अवरूद्ध करती हैं। भारत में महिलाओं की संभाव्य क्षमताएँ अप्रयुक्त संसाधन ही रही हैं।

भारत में 20.37% महिलाएँ एमएसएमई स्वामी हैं जो श्रम शक्ति का 23.3% है। इन्हें अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। मैकिन्सी ग्लोबल के अनुसार, श्रम शक्ति में महिलाओं की सहभागिता बढ़ाकर भारत वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में संभावित रूप से 700 बिलियन डॉलर जोड़ सकता है। विनिर्माण और कृषि क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं का प्रतिशत इन्हीं क्षेत्रों में कार्य करने वाले पुरुषों की तुलना में अधिक है। सामान्यतया इन क्षेत्रों को गरीबी से बाहर आने में परिवारों की सहायता करने का श्रेय दिया जाता है। तथापि, वित्त वर्ष 21 में महिलाओं की साक्षरता दर में 8.8% की वृद्धि हुई है जिससे देश के उज्ज्वल भविष्य का पता चलता है।

महिलाओं की अगुवाई वाले कारोबार, अर्थव्यवस्था को अत्यधिक संबल प्रदान करते हैं। भारत में कामकाजी उम्र की महिलाओं की संख्या 432 मिलियन है, साथ ही 13.5-15.7 मिलियन महिला-स्वामित्व वाले कारोबार हैं जो 22-27 मिलियन लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ कारोबारों



Classification: Internal

Y:\yoti\वर्ष 2022-23\Branch Circular\DEC 2022-23\BU-Rural.docx

MUMBAI

O.L. DEPT. H.O.

उपशाखा विभाग प्र. का.

का नियंत्रण महिलाओं के हाथों में हैं। भारतीय महिलाएं स्वतंत्र हैं और उनमें अपना कारोबार शुरू करने की प्रबल प्रेरणा है। बॉस्टन कंलसल्टिंग ग्रुप के अनुसार महिलाओं द्वारा स्थापित उद्यमों ने पाँच वर्ष की अवधि में 10% अधिक संचयी राजस्व सृजित किया है। इन उद्यमों में अधिक समावेशी कार्य-संस्कृति है और इनमें पुरुषों की तुलना में 3 गुना अधिक महिलाएँ नौकरी करती हैं। तथापि, महिला अगुवाई वाले कारोबारों के अगले 5 साल में 90% बढ़ने का अनुमान है।

## 2. भारत सरकार और आरबीआई की पहल

महिलाओं में उद्यमिता की संवृद्धि और विकास की महत्ता को जान कर नाबार्ड ने वर्ष 1992 में "एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोजेक्ट" आरंभ किया जिसमें छः बैंकों की 500 शाखाएँ तथा स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) को बढ़ावा देने के लिए कुछ एनजीओ शामिल थे। 1999 में भारत सरकार ने एसएचजी के गठन और कौशल विकास के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में स्व-रोजगार को बढ़ावा देने के लिए "स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना" (एसजीएसवाई) आरंभ की। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) को नया रूप देकर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) को 1 अप्रैल 2013 (आरबीआई परिपत्र सं.आरबीआई 2012-13/559 दिनांक 27 जून 2013) से तत्काल प्रभाव से आरंभ किया। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) को दिनांक 19 मार्च, 2016 से डीएवाई-एनआरएलएम (दीन दयाल अत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन) नाम दिया गया।

विनियामक प्राधिकरण (भारत सरकार, आरबीआई, नाबार्ड इत्यादि) एसएचजी को वित्तपोषण की कार्यप्रणाली के बारे में समय-समय पर दिशानिर्देश जारी करते हैं। इसके अतिरिक्त, आरबीआई मास्टर परिपत्र सं. आबीआई/2022-23/92 (एफआईडीडी.जीएसएसडी.सीओ.बीसी संख्या 09/09.01.003/2022-23) दिनांक 20 जुलाई 2022 ने एसएचजी में महिला के वित्तपोषण हेतु नए दिशानिर्देश जारी किए,

- क) डीएवाई-एनआरएलएम के तहत प्रत्येक एसएचजी में एक महिला को, यदि वह अन्यथा पात्र है, मुद्रा योजना के तहत ₹.1.00 लाख तक का ऋण दिया जाए।
- ख) महिला एसएचजी सदस्यों को उद्यमी बनने में सहायता करने के लिए, चुनिंदा परिपक्व अच्छा प्रदर्शन करने वाले एसएचजी के (एसएचजी जो कि 2 वर्ष से अधिक पुरानी है और समयानुसार चुकौती सहित बैंक ऋण के कम से कम 1 डोज तक पहुँच हो) व्यक्तिगत सदस्यों को उनकी उधार नीति के अनुसार ₹.10 लाख तक का ऋण प्रदान करना ।
- ग) इंडियन बैंक एसोसिएशन (आईबीए) द्वारा जारी दिशानिर्देश के अनुसार पीएमजेडीवाई खाते रखने वाले एसएचजी सदस्यों की प्रत्येक महिला को ₹. 5000 की ओडी सुविधा प्रदान करना।

उपर्युक्त को सम्मिलित करते हुए, एनआरएलएम और एमओआरडी पदाधिकारियों के साथ हाल ही की बैठक में, उन्होंने आवेदन सृजन करने हेतु एसआरएलएम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने, ब्याज सहायता का लाभ, सीजीटीएमएसई अथवा सीजीएफएमयू शुल्क की प्रतिपूर्ति और ऋणों की वसूली के संबंध में हमें सूचित किया है।



Classification: Internal

Y:\opt\वर्ष 2022-23\Branch Circular\DEC 2022-23\BU-Rural.docx

### 3. योजना की आवश्यकता:

विनियामक प्राधिकरण (भारत सरकार, आरबीआई नाबार्ड इत्यादि) द्वारा जारी दिशानिर्देशों और स्वयं सहायता समूहों में महिलाओं में उद्यमिता को मजबूत करने शिक्षित एवं विकसित करने के आधार पर, हम एसएचजी में व्यक्तिगत रूप से महिलाओं के वित्तपोषण हेतु एक नई योजना शुरू कर रहे हैं। साथ ही, विभिन्न वित्तीय संस्थाओं के पास विविध क्षेत्रों में एकल महिलाओं के वित्तपोषण हेतु पहले से ही योजना है।

बैंक संबंधी कुछ विशेषतायें इस प्रकार हैं -

(राशि करोड़ में)

विवरण	एसबीआई	बीओबी (पूर्व में देना बैंक)	सेंट्रल बैंक
क्वांटम	0.04	0.20	1.00
ब्याज दर	9.40%	10%	8.40%
मार्जिन	10	10-15	20
प्रतिभूति	सीजीएफएमयू	सीजीएफएमयू/सीजीटीएमएसई	सीजीटीएमएसई

# उपर्युक्त में से एसबीआई एसएचजी की एकल महिला सदस्य का वित्तपोषण कर रहा है और अन्य बैंक के पास महिला उद्यमियों के वित्तपोषण हेतु योजना है।

हमारे पास क्रेडिट लिंकड एवं नॉन क्रेडिट लिंक एसएचजी खातों की बहुत संभावना है। साथ ही एसएचजी पोर्टफोलियो में एनपीए प्रतिशत बहुत कम है। उदाहरण टेबल I एवं टेबल II में निम्नलिखित रूप में है

#### टेबल-I

विवरण	एसएचजी संख्या	लगभग सदस्य *
नॉन क्रेडिट लिंकड महिला एसएचजी	4,70,071	47,00,710
क्रेडिट लिंकड महिला एसएचजी	2,23,870	22,38,700

# प्रति एसएचजी न्यूनतम 10 सदस्य मानते हुए अनुमानित

#### टेबल-II

(राशि करोड़ में)

विवरण	वर्ष			यथा 30.11.2022
	2020	2021	2022	
एसएचजी बकाया	1908.10	2322.38	3632.55	5142.77
कुल कृषि अग्रिमों में हिस्सेदारी का प्रतिशत	3.79%	4.17%	5.71%	7.31%
एनपीए	138.19	148.32	158.83	165.37
एसएचजी पोर्टफोलियो का एनपीए प्रतिशत	7.24%	6.39%	4.73%	3.21%



Classification: Internal

Y:\yoti\वर्ष 2022-23\Branch Circular\DEC 2022-23\BU-Rural.docx

उक्त को ध्यान में रखते हुए हम स्टार सखी योजना (एसएसएस) नामक नई योजना विकसित कर रहे हैं, जिसमें दो खंड हैं:

1. आरबीआई और एनआरएलएम दिशानिर्देशों के आधार पर डीएवाई-एनआरएलएम एसएचजी से एकल महिलाओं का वित्तपोषण
2. एकल महिला सदस्य का वित्तपोषण जिसको ऊपर कवर नहीं किया गया है
5. हमें एनआरएलएम अधिकारियों द्वारा सूचित किया गया है कि संबंधित एसआरएलएम सदस्यों को अतिरिक्त लाभ प्रदान किया जाएगा यदि बैंक ने उनके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसलिए, हम सभी गैर-सरकारी संगठनों/अंचलों को सूचित करते हैं कि वे समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए संबंधित एसआरएलएम से संपर्क करें (मसौदा समझौता ज्ञापन प्रति अनुलग्नक सी-1 के रूप में संलग्न है)। सीआरएमसी ने दिनांक 21.12.2022 की अपनी बैठक में एनबीजी जीएम को संबंधित एसआरएलएम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत किया (एमओयू पर हस्ताक्षर करने के लिए राज्य और प्राधिकारी की सूची अनुलग्नक सी-2 में उल्लिखित है)।
6. शाखाओं के सुलभ उपयोग हेतु आवेदन और प्रस्ताव के लिए मानक प्रारूप क्रमशः अनुलग्नक डी और डी-1 के रूप में संलग्न हैं।
7. ये दिशानिर्देश शाखाओं को इस क्षेत्र को आसानी से समझने और बेहतर टीएटी प्राप्त करने में मदद करेंगे। वित्तपोषण में केंद्रित दृष्टिकोण, प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को ऋण और आय वृद्धि के लक्ष्यों की प्राप्ति में तेजी लाएगा। योजना के दिशा-निर्देशों का ब्यौरा अनुलग्नक ए, बी, सी और डी के रूप में निम्नानुसार संलग्न है

अनुलग्नक-ए	डीएवाई-एनआरएलएम एसएचजी से एकल महिला के वित्तपोषण के लिए दिशानिर्देश
अनुलग्नक-बी	एकल महिला एसएचजी के वित्तपोषण के लिए दिशानिर्देश
अनुलग्नक-सी	एसआरएलएम के साथ समझौता ज्ञापन के लिए दिशानिर्देश (अनुबंध सी, सी-1 और सी-2 के साथ)
अनुलग्नक-डी	आवेदन के लिए मानक प्रारूप (अनुबंध डी) और प्रस्ताव (अनुबंध डी-1)

8. सीआरएमसी ने दिनांक 21.12.2022 की अपनी बैठक में योजना के दिशा-निर्देशों को अनुमोदित किया है। सभी शाखाओं को सूचित किया जाता है कि वे कड़ाईपूर्वक अनुपालन के लिए दिशानिर्देशों का पालन करें।

9. कृपया अपने आंचलिक/एनबीजी कार्यालय के माध्यम से किसी भी स्पष्टीकरण/संदेह के लिए हमें संदर्भित करने में संकोच न करें।






(नितिन देशपांडे)

महाप्रबंधक

Classification: Internal

Y:\yod\वर्ष 2022-23\Branch Circular\DEC 2022-23\BU-Rural.docx



 <b>Bank of India Head Office</b>	<b>BU - Rural</b>
Branch Circular No. 116/241	<b>Sub: Rural/ 2022-23/</b>
<b>Sub-subject: General/</b>	
Ref : HO/Rural/YJJ/ 23	Date: 03.01.2023

**CIRCULAR TO ALL BRANCHES / OFFICES**

**STAR SAKHI SCHEME (SSS)  
- Scheme for Financing to Individual  
Member of Woman of SHGs**

=====

**1. Introduction:**

India's growth story has left behind a key demographic factor i.e **women**. Despite improvements in social parameters, India's growth does not translate to the economic inclusion and development of women. Rather, women's participation in the labour force has stagnated and is expected to decline further because of labour trends, technological disruption and constraining social barriers. Women's socioeconomic role goes unrecognised in India. Most women work as unpaid caregivers, household managers or in other home-based positions; only a minority work outside the house. While women are better educated and enjoy improved healthcare than before, they continue to face structural, social and economic barriers to paid employment. That limits women's individual economic advancement and constrains India's social and economic progress. Women's potential remains as an untapped resource in the country.

In India 20.37% of women are MSME owners which account for 23.3% of the labour force. They are considered to be the backbone of the economy. According to McKinsey Global, India can potentially add US\$ 700 billion to global GDP by increasing women's participation in the labour force. The percentage of women working in the manufacturing and agriculture sector is higher than that of men. These sectors are usually credited with helping families come out of poverty and contributing to higher household income. Moreover, literacy rates among women grew at 8.8% in FY21, which further highlights the bright prospects of the country.

Women-led businesses provide a great impetus to the economy. India has 432 million working-age women and 13.5 –15.7 million women-owned businesses that provide direct employment to 22–27 million people. In addition, a number of businesses are being controlled by women. Indian women are independent and have a strong motivation to start their own business. According to Boston Consulting Group, enterprises founded by women generate 10% more cumulative revenue over a five-year period. These enterprises have a more inclusive work culture and employ 3x more women than men. Moreover, women-led businesses are estimated to grow 90% in the next five years.

**2. Government of India and RBI initiative:**

Realizing the importance of growth and development of entrepreneurship in women NABARD has launched the 'SHG Bank Linkage Project' in year 1992 involving 500 branches of six banks and few NGOs for promotion of Self Help Groups (SHGs). In 1999, Government of India introduced 'Swarnjayanti Gram Swarozgar Yojana' (SGSY) to promote self-employment in rural areas through formation and skill development of SHGs. The Ministry of Rural Development (MoRD), Government of India launched the National Rural Livelihood Mission (NRLM) by revamping 'Swarnjayanti Gram Swarozgar Yojana' (SGSY) with effect from 1<sup>st</sup> April 2013 (RBI Circular No.RBI/2012-13/ 559 dated 27 June 2013). NRLM was renamed as DAY-NRLM (Deendayal Antyodaya Yojana - National Rural Livelihood Mission) w.e.f. March 19, 2016.



Regulatory authorities (GOI, RBI, NABARD, etc.) periodically issue guidelines about the modus operandi of financing to SHGs. Further, RBI Master Circular No. RBI/2022-23/92 (FIDD.GSSD.CO. BC.No.09/ 09.01.003/2022-23) dated July 20, 2022 introduced new guidelines for financing individual woman in SHGs,

- a) One Woman in every SHG under DAY-NRLM may be provided a loan upto Rs.1.00 Lakh under MUDRA Scheme, if otherwise eligible
- b) In order to facilitate women SHG members to graduate to entrepreneurs, extending loans up to ₹10 lakh to individual members of select matured well performing SHGs (SHGs which are more than 2 years old and have accessed at least one dose of bank loan with timely repayment) as per their lending policy.
- c) OD facility of ₹5000 to every woman SHG member having PMJDY account in accordance with the guidelines issued by Indian Banks' Association (IBA).

Including above, recent meeting with NRLM and MoRD officials, They advise us to sign MoU with SRLM for application generation, benefit of Interest Subvention, Reimbursement of CGTMSE or CGFMU fees and recovery of loans.

### 3. Need of Scheme:

Based on the guidelines issued by Regulatory authorities (GOI, RBI, NABARD, etc.) and strengthening, education and developing entrepreneurship in women of the Self Help Groups (SHGs) we are launching a new scheme for financing individual woman in SHGs. Also, various Financial institutions are already having scheme for financing individual woman in various sectors. Few banks feature is mentioned below,

Particular	(Amount in crore)		
	SBI	BOB (Former Dena Bank)	Central Bank
Quantum	0.04	0.20	1.00
ROI	9.40%	10%	8.40%
Margin	10	10-15	20
Security	CGFMU	CGFMU/CGTMSE	CGTMSE

#Out of above SBI is financing to Individual Woman Member of SHGs and other bank have scheme for financing women entrepreneurs.

We have huge potential of Credit linked and Non Credit linked SHG accounts. As well NPA percentage is very low in SHG portfolio. Illustration is mentioned below in Table I and Table II,

**Table: - I**

Particular	No of SHG	Approx. Member*
Non Credit Linked Women SHGs	4,70,071	47,00,710
Credit Linked Women SHGs	2,23,870	22,38,700

\* Estimated by considering min. 10 member per SHG

**Table: - II**

(Amount in crore)

Particulars	Year			As on 30.11.2022
	2020	2021	2022	
SHG O/s	1908.10	2322.38	3632.55	5142.77
% share to total agri. advances	3.79%	4.17%	5.71%	7.31%
NPA	138.19	148.32	158.83	165.37
% of NPA to SHG portfolio	7.24%	6.39%	4.73%	3.21%

By considering the same we are developing new scheme named as STAR SAKHI SCHEME (SSS) with two segment:

1. Financing Individual Woman from DAY-NRLM SHG's based on RBI and NRLM guideline
2. Financing Individual Woman member not covered above

5. We have been informed by NRLM authorities that respective SRLM will provide additional benefit to the members in case bank signed MoU with them. Hence, we advise all NBGs/Zones to approach the respective SRLM for signing the MoU (Draft MoU copy attached as Annexure C-I). CRMC in its meeting dated 21.12.2022 authorized NBG GMs to sign MoU with respective SRLMs (List of State and Authority to sign MoU is mentioned in Annexure C-II).

6. Standard Formats for Application and Proposal are appended as annexure D & D-I respectively for ready use by the branches.

7. These guidelines will help the branches to easily comprehend this sector and achieve improved TAT. A focused approach in financing will expedite achievement of priority sector lending and income growth. The details of the scheme guidelines are enclosed as Annexures A, B, C and D as under:

Annexure-A	Guidelines for Financing Individual Woman from DAY-NRLM SHG's
Annexure-B	Guidelines for Financing Individual Woman SHG's
Annexure-C	Guidelines for MOU with SRLM (along with Annexure C,C-I & C-II)
Annexure-D	Standard Formats for Application (Annexure D) and Proposal (Annexure D-I)

8. The scheme guidelines have been approved by CRMC in its meeting dated 21.12.2022. All branches are advised to follow the guidelines for meticulous compliance.

9. Please do not hesitate to refer to us for any clarifications/ doubts through your Zonal/ NBG Office.



  
(NITIN DESHPANDE)  
GENERAL MANAGER



## Annexure-A

### Guidelines for Financing Individual Woman from DAY-NRLM SHGs:-

Sl. No	Parameters	Description									
1	Name of Scheme	<b>Star Sakhi Scheme (SSS)</b>									
2	Objective	To facilitate, encourage and empower women to graduate themselves as entrepreneurs.									
3	Eligibility	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Woman from Non Credit Linked &amp; Credit Linked SHG sponsored by DAY-NRLM.</li> <li>2. Individual woman member must be above 18 years of age</li> </ol>									
4	Purpose	To provide need-based financial assistance to enterprising woman for all activities eligible under MUDRA.									
5	Constitution	Individual Woman and Proprietorship firm									
6	Quantum of Finance	<ol style="list-style-type: none"> <li>A. Maximum Rs.1.00 Lakh for Non Credit Linked woman SHGs member or woman member not covered under point B.</li> <li>B. Maximum Rs.10.00 Lakh for Credit Linked woman SHGs (SHGs which are more than 2 years old and have accessed at least one dose of bank Loan with timely repayment)</li> </ol>									
7	Margin	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Up to Rs.0.50 Lakh : NIL</li> <li>• Above Rs.0.50 Lakh to Rs.10.00 Lakh : 15%</li> </ul>									
8	Type of Facility Facilities	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Demand loan /Term Loan</li> <li>• Cash Credit / Over Draft</li> <li>• Non Fund based i.e. LC/BG</li> </ul>									
9	Moratorium	Maximum 18 Months based on the activity to be undertaken									
10	Service Charges	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Range Limit</th> <th>Service Charges</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Upto Rs.5.00 Lakh</td> <td>NIL</td> </tr> <tr> <td>Above Rs.5.00 Lakh to Rs.10.00 Lakh</td> <td>Processing Charges flat Rs.1000/-</td> </tr> </tbody> </table> <p># All other charge are waived under the scheme.</p>	Range Limit	Service Charges	Upto Rs.5.00 Lakh	NIL	Above Rs.5.00 Lakh to Rs.10.00 Lakh	Processing Charges flat Rs.1000/-			
Range Limit	Service Charges										
Upto Rs.5.00 Lakh	NIL										
Above Rs.5.00 Lakh to Rs.10.00 Lakh	Processing Charges flat Rs.1000/-										
11	Security	<p><u>Primary</u>- The limit shall be secured by way of first charge on the assets created out of our bank finance.</p> <p><u>Collateral</u> – NIL</p> <p>All a/c's are mandatorily covered under CGFMU.</p>									
12	Rate of Interest	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Limits</th> <th>For all eligible agriculture activities/ units (Except Food and Agro)</th> <th>For all MSME and Food Agro units under agriculture</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Up to Rs.3.00 Lakh</td> <td>One year MCLR+ BSS (0.30%) + Spread (0.00 %)</td> <td>One year RBLR+ Spread (0.00 %)</td> </tr> <tr> <td>Above Rs.3.00 Lakh up to 10.00 Lakh</td> <td>One year MCLR+ BSS (0.30%) + Spread (0.50%)</td> <td>One year RBLR+ Spread (0.50%)</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Note:</b> - No further ROI concession to be given including under Priyadarshani Yojana</p>	Limits	For all eligible agriculture activities/ units (Except Food and Agro)	For all MSME and Food Agro units under agriculture	Up to Rs.3.00 Lakh	One year MCLR+ BSS (0.30%) + Spread (0.00 %)	One year RBLR+ Spread (0.00 %)	Above Rs.3.00 Lakh up to 10.00 Lakh	One year MCLR+ BSS (0.30%) + Spread (0.50%)	One year RBLR+ Spread (0.50%)
Limits	For all eligible agriculture activities/ units (Except Food and Agro)	For all MSME and Food Agro units under agriculture									
Up to Rs.3.00 Lakh	One year MCLR+ BSS (0.30%) + Spread (0.00 %)	One year RBLR+ Spread (0.00 %)									
Above Rs.3.00 Lakh up to 10.00 Lakh	One year MCLR+ BSS (0.30%) + Spread (0.50%)	One year RBLR+ Spread (0.50%)									
13	Penal Charges	Penal Interest@2% per annum for the defaulted Portion for the period of Default									



14	Tenure of Loan/Repayment	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Demand Loan</b> : Maximum tenure is 36 months (Monthly installment or EMI)</li> <li>• <b>Term Loan</b>: Maximum tenure is 84 months (Monthly installment or EMI) Including Moratorium Period.</li> <li>• <b>Cash Credit/OD facility</b>: On Demand- Subject to annual review. Interest during moratorium period may be capitalized or recovered depending upon basis of income of the applicant.</li> </ul>
15	Sanctioning Authority	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>MSME Advances</b>: Branch Manager /Designated Credit Manager</li> <li>• <b>Agriculture Advances</b>: SKVK for all tagged branches and Branch Manager/ Designated Credit Manager for untagged branches.</li> </ul>
16	Due diligence	All necessary due diligence as per EKYC norms are to be carried out and ensure that the findings are satisfactory. Branches to follow the extant guidelines related to due diligence on KYC, Inspection, valuation, assessment etc. revised by HO from time to time. The documentary record must be kept along with loan documents as an evidence of compliance of all laid down guidelines.
17	CIBIL	Generation of CIBIL report is mandatory. It is preferably to have satisfactory CIBIL Finding. However, the sanctioning authority can take call in case of unsatisfactory CIBIL due to reason beyond the control of borrower giving valid justifications.
18	Credit Rating	Credit rating is exempted for limit upto Rs.10.00 Lakh. However for easy assessment we are providing credit rating sheet as <b>Appendix I</b> . For Consideration of the application under this scheme borrower should score more than 20 marks.
19	Disbursement	Disbursement should be done in phase manner or lump-sum depending on the nature. Disbursement should be made preferably by way of DD/Pay Slip/NEFT/RTGS to the supplier.
20	Registration of charge with CERSAI	Charges with CERSAI to be registered as per guidelines of the Bank.
21	Guarantee Cover Codes and Scheme identifier	<p>Guarantee Cover Code: 11- Credit Guarantee Fund for Micro Units (CGFMU) is mandatory for all advances under the scheme. Label Code : Star Sakhi Scheme – Non MoU Star Sakhi Scheme – MoU</p> <p>It will be mandatory for all branches to incorporate the same while opening account in Universal Banking Solution (UBS).</p>
22	Insurance	All Assets Charged to the bank should be adequately Insured
23	Monitoring & follow-up	<p><b>Pre- Sanction :-</b> Branch Officials should carryout pre sanction inspection visit while appraising the loan</p> <p><b>Post Sanction :-</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) End use of fund is to be ensured as per extant guidelines during post sanction inspection</li> <li>(ii) Periodical post sanction inspection/ visit shall be made</li> <li>(iii) All such report to be kept on record</li> </ul>

24	IRAC Norm	A loan granted under the scheme will be treated as Non-performing Asset (NPA), if interest and/ or instalment of principal remains overdue for a period of more than 90 days.
25	Classification	As per HOBC No.116/186 dated 29.10.2022, regarding Master Directions - Priority Sector lending (PSL) - Targets and Classification. [RBI Master Directions FIDD.CO.Plan.BC.5/04.09.01/2020-21 dated September 04, 2020 updated as on October 20, 2022 (RBI/FIDD/2020-21/72)]. Loans are allowed to be classified under Priority Sector Lending under the respective categories Agriculture & MSME.
26	CGFMU Guarantee fee payment and Invocation of guarantee	<p><b>Guarantee fee payment:</b> MSME Department pull data every quarter on the basis of guarantee cover code -11 entered at the time of opening of the account and submit information to NCGTC for guarantee cover.</p> <p>The amount will be debited from the ZO GENSUS accounts of respective Zones and the list of account with guarantee fees details will be sent to Zone for recovery from borrowers. The Zones are advised to debit the Office Account of the respective branch and furnish the list of accounts provided by Head Office. The branch will reconcile the account by debiting the account of borrowers.</p> <p>The Guarantee cover will commence from the date of payment of guarantee fee and shall run through the agreed tenure of payment of micro loan or the termination date of the portfolio, whichever is earlier, subject to yearly renewal of the guarantee portfolio.</p> <p><b>Invocation of guarantee:</b> The bank may invoke the guarantee in respect of the 'amount of default' out of the crystallized portfolio of micro loans, subject to the condition of first loss guarantee, after one year from the date of crystallization of the portfolio and thereafter, at the end of every financial year.</p> <p>Amount received as interim/final settlement will be distributed to the zones as per their NPA portfolio. The list of accounts and claim amount will be provided to the Zones by Head Office. The Zones are advised to remit the claim amount to the branches for credit into the respective NPA accounts.</p> <p>Ref. Branch to follow the guidelines circulated by SME department vide. HOBC 111/19 dated 05.05.2017.</p>
27	Processing of Loan and Digitalisation	<p>The branches should process loan proposal for financing in prescribe format manually, till the implementation of end-to-end digitalization. Automated process of the product in end to end digitalization will be advised to the branches separately.</p> <p>Process of digitalization of Shishu, Kishor and Tarun is at final stage. In case of digital process modalities as designed for a specific digital journey will be applicable.</p>



28	MOU with State Rural Livelihood Mission (SRLM)	<p>National Rural Livelihood Mission – a Flagship programme of Government of India is being implemented through State Rural Livelihood Mission (SRLM) of different state governments.</p> <p>SRLM is assisting the Women of SHGs through imparting financial literacy, extending counselling services on savings, credit and training on micro investment, planning enabled in capacity building.</p> <p>The mission will also extend support to the Bank at their respective State levels for improving quality services to poor clients including follow-up for recovery of overdues, if any by utilizing the services to customer relationship manager (i.e. Bank Mitra/Sakhi) with every Bank branch involved in financing of Women of SHGs.</p> <p>State Rural Livelihood Mission (SRLM) upon signing of MoU extend following benefits to us subject to sanction limit not less than Rs.0.75 lakh to individual member,</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Actual Credit Guarantee Charges on loans upto Rs.5 lakh for a maximum period of 5 years will be reimbursed</li> <li>2. SHG member will be extended the benefit of interest subvention @ 2% on maximum loan outstanding of Rs.1.5 lakh for a maximum period of 3 years.</li> </ol> <p>Guidelines for entering into MOU with State Governments alongwith draft copy of MOU duly approved by Legal Department, HO is enclosed as <b>Annexures C</b>.</p>
29	Other guidelines	<p>i) It should be ensured that the requirement is need based.</p> <p>ii) Viability aspects of projects should be looked into as per extant guidelines.</p> <p>iii) Reporting under PSRS as per extant norms.</p> <p>iv) Records such as pre/post sales, inflow of stock &amp; book debts, bills/vouchers if applicable and available, and any other proof should be kept in file provided for audit.</p> <p>v) Guidelines issued through credit policy of Agri. lending and MSME policy shall be adhered.</p>





## Guidelines for Financing Individual Woman of SHGs:-

Sl. No	Parameters	Description									
1	Name of Scheme	<b>Star Sakhi Scheme (SSS)</b>									
2	Objective	To facilitate, encourage and empower women to graduate themselves as entrepreneurs.									
3	Eligibility	1. Woman from Non Credit Linked & Credit Linked SHG 2. Individual woman member must be above 18 years of age									
4	Purpose	To provide need-based financial assistance to enterprising woman for all activities eligible under MUDRA.									
5	Constitution	Individual Woman and Proprietorship firm									
6	Quantum of Finance	Maximum : Rs.10.00 Lakh									
7	Margin	<ul style="list-style-type: none"> <li>Up to Rs.0.50 Lakh : NIL</li> <li>Above Rs.0.50 Lakh to Rs.10.00 Lakh : 15%</li> </ul>									
8	Type of Facility Facilities	<ul style="list-style-type: none"> <li>Demand loan /Term Loan</li> <li>Cash Credit / Over Draft</li> <li>Non Fund based i.e. LC/BG</li> </ul>									
9	Moratorium	Maximum 18 Months based on the activity to be undertaken									
10	Service Charges	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Range Limit</th> <th>Service Charges</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Upto Rs.5.00 Lakh</td> <td>NIL</td> </tr> <tr> <td>Above Rs.5.00 Lakh to Rs.10.00 Lakh</td> <td>Processing Charges flat Rs.1000/-</td> </tr> </tbody> </table> <p># All other charge are waived under the scheme.</p>	Range Limit	Service Charges	Upto Rs.5.00 Lakh	NIL	Above Rs.5.00 Lakh to Rs.10.00 Lakh	Processing Charges flat Rs.1000/-			
Range Limit	Service Charges										
Upto Rs.5.00 Lakh	NIL										
Above Rs.5.00 Lakh to Rs.10.00 Lakh	Processing Charges flat Rs.1000/-										
11	Security	<p><u>Primary</u>- The limit shall be secured by way of first charge on the assets created out of our bank finance.</p> <p><u>Collateral</u> – NIL</p> <p>All a/c's are mandatorily covered under CGFMU.</p>									
12	Rate of Interest	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Limits</th> <th>For all eligible agriculture activities/ units (Except Food and Agro)</th> <th>For all MSME and Food Agro units under agriculture</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Up to Rs.3.00 Lakh</td> <td>One year MCLR+ BSS (0.30%) + Spread (0.00 %)</td> <td>One year RBLR+ Spread (0.00 %)</td> </tr> <tr> <td>Above Rs.3.00 Lakh up to 10.00 Lakh</td> <td>One year MCLR+ BSS (0.30%) + Spread (0.50%)</td> <td>One year RBLR+ Spread (0.50%)</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Note:</b> - No further ROI concession to be given including under Priyadarshani Yojana</p>	Limits	For all eligible agriculture activities/ units (Except Food and Agro)	For all MSME and Food Agro units under agriculture	Up to Rs.3.00 Lakh	One year MCLR+ BSS (0.30%) + Spread (0.00 %)	One year RBLR+ Spread (0.00 %)	Above Rs.3.00 Lakh up to 10.00 Lakh	One year MCLR+ BSS (0.30%) + Spread (0.50%)	One year RBLR+ Spread (0.50%)
Limits	For all eligible agriculture activities/ units (Except Food and Agro)	For all MSME and Food Agro units under agriculture									
Up to Rs.3.00 Lakh	One year MCLR+ BSS (0.30%) + Spread (0.00 %)	One year RBLR+ Spread (0.00 %)									
Above Rs.3.00 Lakh up to 10.00 Lakh	One year MCLR+ BSS (0.30%) + Spread (0.50%)	One year RBLR+ Spread (0.50%)									
13	Penal Charges	Penal Interest@2% per annum for the defaulted Portion for the period of Default									
14	Tenure of Loan/Repayment	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Demand Loan</b> : Maximum tenure is 36 months (Monthly installment or EMI)</li> <li><b>Term Loan</b>: Maximum tenure is 84 months (Monthly installment or EMI) Including Moratorium Period.</li> <li><b>Cash Credit/OD facility</b>: On Demand- Subject to annual review.</li> </ul> <p>Interest during moratorium period may be capitalized or recovered depending upon basis of income of the applicant.</p>									





15	Sanctioning Authority	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>MSME Advances:</b> Branch Manager /Designated Credit Manager</li> <li>• <b>Agriculture Advances:</b> SKVK for all tagged branches and Branch Manager/ Designated Credit Manager for untagged branches.</li> </ul>
16	Due diligence	All necessary due diligence as per EKYC norms are to be carried out and ensure that the findings are satisfactory. Branches to follow the extant guidelines related to due diligence on KYC, Inspection, valuation, assessment etc. revised by HO from time to time. The documentary record must be kept along with loan documents as an evidence of compliance of all laid down guidelines.
17	CIBIL	Generation of CIBIL report is mandatory. It is preferably to have satisfactory CIBIL Finding. However, the sanctioning authority can take call in case of unsatisfactory CIBIL due to reason beyond the control of borrower giving valid justifications.
18	Credit Rating	Credit rating is exempted for limit upto Rs.10.00 Lakh. However for easy assessment we are providing credit rating sheet as <b>Appendix I</b> . For Consideration of the application under this scheme borrower should score more than 20 marks.
19	Disbursement	Disbursement should be done in phase manner or lump-sum depending on the nature. Disbursement should be made preferably by way of DD/Pay Slip/NEFT/RTGS to the supplier.
20	Registration of charge with CERSAI	Charges with CERSAI to be registered as per guidelines of the Bank.
21	Guarantee Cover Codes and Scheme identifier	<p>Guarantee Cover Code: 11- Credit Guarantee Fund for Micro Units (CGFMU) is mandatory for all advances under the scheme. Label Code : Star Sakhi Scheme – Non DAY- NRLM</p> <p>It will be mandatory for all branches to incorporate the same while opening account in Universal Banking Solution (UBS).</p>
22	Insurance	All Assets Charged to the bank should be adequately Insured
23	Monitoring & follow-up	<p><b>Pre- Sanction :-</b> Branch Officials should carryout pre sanction inspection visit while appraising the loan</p> <p><b>Post Sanction :-</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(iv) End use of fund is to be ensured as per extant guidelines during post sanction inspection</li> <li>(v) Periodical post sanction inspection/ visit shall be made</li> <li>(vi) All such report to be kept on record</li> </ul>
24	IRAC Norm	A loan granted under the scheme will be treated as Non-performing Asset (NPA), if interest and/ or instalment of principal remains overdue for a period of more than 90 days.
25	Classification	As per HOB No.116/186 dated 29.10.2022, regarding Master Directions - Priority Sector lending (PSL) - Targets and Classification. [RBI Master Directions FIDD.CO.Plan.BC.5/04.09.01/2020-21 dated September 04, 2020 updated as on October 20, 2022 (RBI/FIDD/2020-21/72)]. Loans are allowed to be classified under Priority Sector Lending under the respective categories Agriculture & MSME.



26	CGFMU Guarantee fee payment and Invocation of guarantee	<p><b>Guarantee fee payment:</b> MSME Department pull data every quarter on the basis of guarantee cover code -11 entered at the time of opening of the account and submit information to NCGTC for guarantee cover.</p> <p>The amount will be debited from the ZO GENSUS accounts of respective Zones and the list of account with guarantee fees details will be sent to Zone for recovery from borrowers. The Zones are advised to debit the Office Account of the respective branch and furnish the list of accounts provided by Head Office. The branch will reconcile the account by debiting the account of borrowers.</p> <p>The Guarantee cover will commence from the date of payment of guarantee fee and shall run through the agreed tenure of payment of micro loan or the termination date of the portfolio, whichever is earlier, subject to yearly renewal of the guarantee portfolio.</p> <p><b>Invocation of guarantee:</b> The bank may invoke the guarantee in respect of the 'amount of default' out of the crystallized portfolio of micro loans, subject to the condition of first loss guarantee, after one year from the date of crystallization of the portfolio and thereafter, at the end of every financial year.</p> <p>Amount received as interim/final settlement will be distributed to the zones as per their NPA portfolio. The list of accounts and claim amount will be provided to the Zones by Head Office. The Zones are advised to remit the claim amount to the branches for credit into the respective NPA accounts.</p> <p>Ref. Branch to follow the guidelines circulated by SME department vide. HOBC 111/19 dated 05.05.2017.</p>
27	Processing of Loan and Digitalisation	<p>The branches should process loan proposal for financing in prescribe format manually, till the implementation of end-to-end digitalization. Automated process of the product in end to end digitalization will be advised to the branches separately.</p> <p>Process of digitalization of Shishu, Kishor and Tarun is at final stage. In case of digital process modalities as designed for a specific digital journey will be applicable.</p>
28	MOU with State Rural Livelihood Mission (SRLM)	Not Applicable. Hence, interest subvention or reimbursement of CGFMU fee will not available.
29	Other guidelines	<p>i) It should be ensured that the requirement is need based.</p> <p>ii) Viability aspects of projects should be looked into as per extant guidelines.</p> <p>iii) Reporting under PSRS as per extant norms.</p> <p>iv) Records such as pre/post sales, inflow of stock &amp; book debts, bills/vouchers if applicable and available, and any other proof should be kept in file provided for audit.</p> <p>v) Guidelines issued through credit policy of Agri. lending and MSME policy shall be adhered.</p>



Bank of India

\_\_\_\_\_ Branch

**RATING SHEET FOR STAR WOMEN ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT  
SCHEME**

Sr. No	Parameter	Eligible Marks	Marks allotted
<b>1</b>	<b>ID Proof</b>	<b>Maximum Mark 5</b>	
i	Passport/Pan Card/ Aadhar Card/Driving license	5	
ii	Pan Card/ Aadhar Card/Driving license	3	
iii	Aadhar Card/Voter ID/any other Govt. Doc	2	
iv	Aadhar Card/Voter ID/any other Doc	1	
<b>2</b>	<b>Age</b>	<b>Maximum Mark 5</b>	
i	18-40	5	
ii	41-50	3	
iii	51-65	2	
iv	Age above 65 years	1	
<b>3</b>	<b>Education qualification</b>	<b>Maximum Mark 5</b>	
i	Post Graduate/Graduate	5	
ii	12 <sup>th</sup> Pass	3	
iii	10 <sup>th</sup> Pass	2	
iv	Under Matriculation	1	
<b>4</b>	<b>Residing at the same place</b>	<b>Maximum Mark 5</b>	
i	5 years and above	5	
ii	3-5 years	3	
iii	2-3 years	2	
iv	Less than 2 years	0	
<b>5</b>	<b>Family Composition/Dependent</b>	<b>Maximum Mark 3</b>	
i	Dependent Less than 3	3	
ii	Dependent 3-5	2	
iii	Dependent More than 5	1	
<b>6</b>	<b>Any Other earning member in family</b>	<b>Maximum Mark 2</b>	
i	Yes	2	
ii	No	0	
<b>7</b>	<b>Existence of Business Unit</b>	<b>Maximum Mark 5</b>	
i	More than 3 Years	5	
ii	1 - 3 years	3	
iii	Less than 1	2	
<b>8</b>	<b>Maintenance transaction in Bank Accounts (last 1 years)</b>	<b>Maximum Mark 5</b>	
i	More Than 50	5	
ii	50-30	3	
iii	30-20	2	
iv	Less than 20	0	



<b>9</b>	<b>Availing financial assistance from Bank/FI</b>	<b>Maximum Mark 5</b>	<b>5</b>
i	More than 5 Years		5
ii	5- 3 years		4
iii	3-1 years		3
iv	6 Months to 1 years		2
V	Less than 6 months		1
<b>10</b>	<b>Bureau Score (CIBIL, Equifax or Experian etc.)</b>	<b>Maximum Mark 5</b>	<b>5</b>
i	800 and above		5
ii	701 - 799		4
iii	650 - 700		3
iv	0/-1		1
v	Less than 650		0
<b>11</b>	<b>Deposit Potential</b>	<b>Maximum Mark 5</b>	<b>5</b>
i	Average Deposit Last one year > 25,000/		5
ii	Average Deposit Last one year > 15- 25,000/		4
iii	Average Deposit Last one year > 10- 15,000/		3
iv	Average Deposit Last one year > 5-10,000/		2
v	Average Deposit Last one year > 5,000/		0
<b>12</b>	<b>Expected Net Annual Income</b>	<b>Maximum Mark 3</b>	<b>3</b>
i	Upto Rs.1.5 Lakh		3
ii	Rs.1.5 lakh – Rs.1.00 lakh		2
iii	Less than Rs.1.00 Lakh		1
<b>13</b>	<b>Skill Certification</b>	<b>Maximum Mark 2</b>	<b>2</b>
i	Yes		2
ii	No		0
	<b>Total Maximum Mark</b>		<b>55</b>
	<b>Less than 20 Mark = should not be considered for loan</b>		





### MOU with State Rural Livelihood Mission (SRLM)

Each State Government will be executing a Memorandum of Understanding (MOU) with the Banks in their respective states with the following objectives:

1. Implement a demonstrable model of direct bank finance to individual SHG member for setting up viable economic enterprises
2. Establish structured process and protocol for extending bank finance to individual SHG member
3. Capacity Building and sensitization of Bank officials and SRLM functionaries towards need of bank finance for women-led enterprise
4. Create/ define new credit products to meet the emerging credit requirements of women-led enterprises

A Memorandum of Understanding with each State Government will be executed separately in order to improve our stake in SHG Women credit linkage programme and encash the opportunity for garnering business at grass root level involving SMECC, SKVKs, Area Managers, Bank Mitras/ Sakhis alongwith branches under supervision of respective Zonal Offices under monitoring of concerned NBGs.

**The following guidelines have to be adopted while implementing the programme:**

- i) The Memorandum of Understanding with State Rural Livelihood Mission at State level will be executed as & when approached by State Level Missions;
- ii) The Power of Attorney holders identified by the General Manager (NBGs) in their respective areas of operation will be authorized to execute the MOU on behalf of the Bank;
- iii) The draft MOU is provided by NRLM and vetted by our Legal Department (Draft MOU is enclosed herein below);
- iv) The tenure of the Memorandum of Understanding will be depend on mutual understanding between bank and SRLM which may be extendable as per need basis, on mutually acceptable terms and conditions.
- v) The NBGs/ Zonal Offices to regularly monitor the progress in their area of operation and review the same during the periodical review meetings of the NBGs/ Zones by Controlling Heads.
- vi) A copy of MOU executed by NBG Offices to be sent to Head Office for our record.

**Salient Feature for signing of MoU:**

- i) SRLM in coordination with Ministry of Rural Development, Government of India will ensure reimbursement of actual charges (if any) towards credit guarantee cover taken for loans sanctioned by banks to identified women members of SHGs as per the following conditions:
  - a) Actual Credit Guarantee Charges as levied by CGTMSE and NCGTC on banks will be reimbursed
  - b) Actual Credit Guarantee Charges on loans upto Rs.5 lakh for a maximum period of 5 years will be reimbursed
  - c) Actual Credit Guarantee Charges with respect to loan accounts belonging to identified women SHG members under SRLM will only be eligible for reimbursement
  - d) Reimbursement of credit guarantee charges for one member will be done only once, subject to the maximum quantum and tenure as mention at point (b)
  - e) Reimbursement of credit guarantee charges will be directly done by Ministry of Rural Development, Govt. of India to the bank subject to submission of requisite information.



ii) SRLM in coordination with Ministry of Rural Development, Govt. of India will ensure to extend benefit of interest subvention to SHG members as per the following conditions:

- a) SHG member will be extended the benefit of interest subvention @ 2% on maximum loan outstanding of Rs.1.5 lakh for a maximum period of 3 years.
- b) Interest subvention will be provided only for the period the account remained standard. No interest subvention will be payable for the period the account remained classified as "NPA" or "out of order" for more than 30 days. In case of account classified as "NPA" subsequently turns as standard asset on account of recovery of overdues, no subvention amount will be payable for the period the account remained classified as "NPA" or "out of order" for more than 30 days.
- c) Benefit of interest subvention to one member will be given only once, subject to the maximum quantum and tenure.
- d) Interest Subvention will be directly credited by Ministry of Rural Development, Govt. of India to the bank, for onward distribution to eligible borrowers, subject to submission of requisite information.

iii) Subvention is applicable only for credit limit sanctioned more than Rs.75000 to identified SHG members.

# For Role and responsibilities of Bank and SRLM please refer format of **MoU point no.3**



**(DRAFT)**  
**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING**

This Memorandum of Understanding (hereinafter referred to as “**MoU**”) is executed at  
..... on this ..... day of December 2022

BETWEEN

..... **State Livelihoods Mission, Department of Rural Development, Government of .....** – represented by the State Mission Director/ Chief Executive Officer, having its office at ..... hereinafter referred to as “**State-SRLM**” (which term or expression unless excluded by the or repugnant to the subject or context shall mean and include its successors-in-office and assignees) of the “**FIRST PARTY**”

AND

Bank of India, a Bank constituted under the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act, 1970 and having its Central Office at ..... Mumbai, Maharashtra and one of its circle office at ..... (hereinafter referred to as the “**Bank**”, which expression shall, unless repugnant to the context or meaning thereof be deemed to mean and include its successors and assignees) of the “**SECOND PARTY**”

Wherever the context so requires, the SRLM and the Bank are sometimes individually referred to as “**Party**” and collectively as “**Parties**” throughout this Agreement and the words Party and Parties shall be construed accordingly.

**About SRLM**

**About Bank of India (BANK)**

**CONTEXT**

Besides agriculture, Nano and micro-enterprises collectively employ more people than any other sector and contribute roughly one-third of India’s GDP. Despite the impressive contribution of such enterprises, one constituency which often remains ignored is – ‘Women-Led Enterprises. There are an estimated 13.5–15.7 million women-owned enterprises in India. Though the number is large in absolute numbers, most of these are very small in size and often do not generate enough incomes. Many of these enterprises have good potential to grow and scale up, but access to formal credit and business support services by these women-owned enterprises remain a significant barrier. Aajeevika – Deendayal Antyodaya Yonja-National Rural Livelihoods Mission (DAY-NRLM) a Govt of India sponsored scheme being implemented in the state of .....through its network of women Self Help Group network have the potential to play a greater role in promotion and growth of women-led enterprises by facilitating access to affordable credit, business support services including mentor-ship and support in accessing markets.





Women Self Help Groups under DAY-NRLM in the state of .....have emerged as a credible institution to channelize credit from formal institutions to women members. Large number of women SHG members has over time diligently used this platform to access small credit and start their own enterprises. Today, many of these enterprises have graduated and need credit in excess of Rs.50,000/- to expand and grow but have out-grown the lending ability of Self-Help Groups. Such enterprises face the dual challenge where their parent SHG is unable to adequately fund their enterprises and direct credit support from formal institutions are difficult to access due to inherent challenges.

Self Help Group generally offer simple credit products to their members for meeting small credit requirements for a short duration. Enterprises particularly those in the growth spiral need credit products which are large in size, for longer duration and customized to their requirements, making them much more complex. Appraisal of such loans, customizing such products and maintaining prudent accounting requires higher capacity and technology backstopping which is currently not available with SHGs.

In order to ensure, emerging women enterprises have access to adequate financing and grow organically, the only alternative is direct financing by mainstream financial institutions.

## PROPOSAL

Both the Parties having identified the need for Bank credit directly to individual women Self-Help Group members (hereinafter referred to as “**SHG member**”) for setting up viable economic enterprises and facilitate orderly growth of the programme in the state of .....and have mutually agreed to enter into this MoU with the following objectives:

1. Implement a demonstrable model of direct bank finance to individual SHG member for setting up viable economic enterprises.
2. Establish structured process and protocol for extending bank finance to individual SHG member.
3. Capacity Building and sensitization of Bank officials and SRLM functionaries towards need of bank finance for women-led enterprise.
4. Create/ define new credit products to meet the emerging credit requirements of women-led enterprises.





**NOW THIS MOU WITNESSETH AND THEREFORE IT IS HEREBY AGREED BY AND BETWEEN ..... AND ..... HERE TO AS FOLLOWS:**

**1. TERM**

This MOU is for a period of 2 (two) years, commencing on the date of signing of this document. This MoU may thereafter be renewed with terms and conditions mutually agreed by both parties in writing.

**2. SCOPE OF WORK**

It is envisaged that during this engagement, **SRLM** and Bank will jointly ensure:

1. Identification of districts/blocks for purpose of implementing the said intervention
2. Develop appropriate credit product for women SHG members to meet their credit requirement for enterprises
3. Ensure access to adequate finance to women SHG members as per milestones mentioned in annexure-1.
4. Design, develop, test, and institutionalize a structured process and protocol for identification & assessment of eligible SHG members; sourcing of application including documentation; Credit appraisal and assessment criteria and process; post credit disbursement and follow-up. Entire process/ protocol will be documented as mutually agreed upon by **SRLM** and **Bank** and will be a part of this MoU.
5. Conceptualize and design an IT enabled system from submission of application and monitoring of disbursement and post-disbursement account status

**3. ROLES AND RESPONSIBILITIES**

**[A] Role of SRLM**

1. SRLM will designate nodal persons at state/ district/block/ sub-block level for purpose of coordination for the proposed intervention
2. SRLM will train and deploy personnel under SRLM and Community Cadres in the identified geographies to take up assigned tasks under the proposed intervention
3. SRLM will conduct initial assessment to identify potential SHG members seeking individual Loan from bank for setting up/ expand their economic enterprises.
4. SRLM will conduct initial orientation of all identified SHG members and make them aware of various requirements for seeking direct credit from banks
5. SRLM through its field functionaries (personnel under SRLM and community cadres) will assist SHG member in preparation of loan proposal including completion of documentation formalities as per protocols agreed with bank.
6. SRLM will provide assistance to SHG members in formalization of the enterprises as may be required
7. SRLM will assist bank in accessing necessary/ relevant information related to the identified members required for appraisal and assessment of proposal by bank



8. SRLM in coordination with Ministry of Rural Development, Govt of India will ensure reimbursement of actual charges (if any) towards credit guarantee cover taken for loans sanctioned by banks to identified women members of SHGs as per the following conditions:
  - a) Actual Credit Guarantee Charges as levied by CGTMSE and NCGTC on banks will be reimbursed
  - b) Actual Credit Guarantee Charges on loans upto Rs 5 lakhs for a maximum period of 5 years will be reimbursed
  - c) Actual Credit Guarantee Charges with respect to loan accounts belonging to identified women SHG members under SRLM will only be eligible for reimbursement
  - d) Reimbursement of credit guarantee charges for one member will be done only once, subject to the maximum quantum and tenure as mention at point (b)
  - e) Reimbursement of credit guarantee charges will be directly done by Ministry of Rural Development, Govt of India to the bank subject to submission of requisite information.
9. SRLM through its field functionaries will monitor the utilization of loans extended by bank
10. SRLM through its field functionaries will monitor the timely repayment of loans extended by bank
11. SRLM in coordination with Ministry of Rural Development, Govt of India will ensure to extend benefit of interest subvention to SHG members as per the following conditions:
  - a) SHG member will be extended the benefit of interest subvention @ 2% on maximum loan outstanding of Rs.1.5 lakh for a maximum period of 3 years.
  - b) Interest subvention will be provided only for the period the account remained standard. No interest subvention will be payable for the period the account remained classified as "NPA" or "out of order" for more than 30 days. In case of account classified as "NPA" subsequently turns as standard asset on account of recovery of overdues, no subvention amount will be payable for the period the account remained classified as "NPA" or "out of order" for more than 30 days.
  - c) Benefit of interest subvention to one member will be given only once, subject to the maximum quantum and tenure as mention at point (b)
  - d) Interest Subvention will be directly credited by Ministry of Rural Development, Govt of India to the bank, for onward distribution to eligible borrowers, subject to submission of requisite information.
12. SRLM will perform any other task in mutual agreement with bank, which is in interest of the intervention and the larger programme.

#### **[B] Role of BANK**

1. BANK will designate appropriate official for purpose of coordination for the intervention
2. BANK will identify and designate nodal branches/ credit hubs for the proposed intervention
3. BANK will define a specific credit product for the intervention as per requirements (involving both investment and working capital) of individual women SHG members
4. BANK will process and dispose all applications submitted at the designated branches/ credit hubs within 15 days of submission



5. BANK, at its discretion, will extend adequate credit of not less than Rs.75000/- to identified SHG members if found eligible as per the laid down conditions subject to fulfilment of Banks guidelines in this regard
6. BANK, at its discretion, will extend loans for viable economic enterprises in agri (except subsistence agriculture); agri-allied, MSME and non-farm sectors subject to fulfilment of Banks guidelines in this regard.
7. BANK will provide loan passbook/ loan account statement to borrowers at the request of borrowers.
8. BANK may endeavour enrolment of all eligible borrowers under life (PMJJBY) and accidental insurance (PMSBY) schemes before disbursement of loan.
9. BANK will coordinate with SRLM for orientation of the eligible borrowers
10. BANK will coordinate with SRLM for orientation and training of SRLM functionaries (SRLM personnel and community cadres)
11. BANK will conduct orientation of bank officials connected with the intervention in coordination with SRLM
12. BANK will closely engage with SRLM and community institutions to ensure timely repayment of loan.
13. BANK will furnish information related to number of loans sanctioned, amount of loans sanctioned; status of each account; overdues if any to SRLM for purpose of monitoring on monthly basis
14. BANK will furnish requisite information and submit claims for reimbursement of credit guarantee charges to Ministry of Rural Development, Govt of India as per laid down procedure
15. BANK will furnish requisite information and submit claims for interest subvention for eligible borrowers to Ministry of Rural Development, Govt of India as per laid down procedure
16. BANK will further pass on the interest subvention amount as received from Ministry of Rural Development, Govt of India to respective accounts of eligible borrowers
17. BANK will perform any other task in mutual agreement with SRLM, which is in interest of the intervention and the larger programme.

#### **4. ASSIGNMENT**

Neither Party shall assign any rights, duties, or obligations under this Agreement to any other Party, without the written prior permission of the other Party.

#### **5. MONITORING OF PROGRESS**

A monitoring committee comprising of State Mission Director/ Chief Executive Officer – SRLM; Zonal/Regional Head of Bank and other officials/ functionaries from SRLM and Bank will be constituted to monitor the progress of the initiative and resolve any operational difficulties. The monitoring committee will meet every month during the first two quarters of the intervention and every two months in the subsequent quarters. Reports as compiled by SRLM including information as shared by bank will be presented in the meeting. Decision regarding any modification in implementation processes may be taken by the committee. Final compiled reports of the progress will be forwarded by the committee to the Head Office of Bank and Ministry of Rural Development, Govt of India.

#### **6. TERMINATION OF MOU**

The MOU can be terminated earlier by either party after giving a written prior-notice of not less than 30 days.





## **7. DISPUTES RESOLUTION**

In event of a dispute arising between the Parties as to matters covered by this MoU or the validity, enforceability, or interpretation thereof (each, a "Dispute"), attempts will be made to mutually resolve such Disputes. In case both parties are unable to amicably settle such disputes, failing which, such matter will be referred to Head Office of Bank and Ministry of Rural Development, Govt of India for necessary guidance. Directions from Head Office of Bank and Ministry of Rural Development, Govt of India will be final and binding on both parties.

This Agreement shall be governed by, and shall be construed in accordance with Indian laws.

All claims, differences and disputes, arising out of or in relation to this Agreement shall fall within the exclusive jurisdiction of the Courts at ----- only.

**IN WITNESSES WHERE OF** the Parties hereto have executed this MoU in duplicate as of the date set out here under:

<b>for Bank</b>	<b>for SRLM</b>
<b>Regional Head, Authorised Signatory</b>	<b>State Mission Director/Chief Executive Officer, SRLM, Authorised Signatory</b>
<b>Witness:</b>	<b>Witness:</b>
1.	1.
2.	2.





**Agreed Milestones on financing individual SHG members for economic enterprises**

<b>Period</b>	<b>No of SHG members financed</b>
<b>FY 2022-23</b>	
<b>Q3 (Oct 2022 – Dec 2022)</b>	
<b>Q4 (Jan 2023 – Mar 2023)</b>	
<b>FY 2023-24</b>	
<b>Q1 (Apr 2023 – Jun 2023)</b>	
<b>Q2 (Jul 2023 – Sept 2024)</b>	
<b>Q3 (Oct 2023 – Dec 2023)</b>	
<b>Q4 (Jan 2024 – Mar 2024)</b>	

The milestones mentioned may be mutually modified with written consent from both parties involved



**LIST OF STATES AND COMPETENT AUTHORITY TO EXECUTE THE MOU WITH CONCERNED STATE GOVERNMENT**

SR NO.	STATE	AUTHORITY TO EXECUTE THE MOU
1	ANDHRA PRADESH	GM,NBG(SOUTH)
2	ARUNACHAL PRADESH	GM,NBG(EAST)
3	ASSAM	GM,NBG(EAST)
4	BIHAR	GM,NBG(BIHAR)
5	CHATTISGARH	GM,NBG (MP-CH)
6	GOA	GM,NBG(WEST-I)
7	GUJARAT	GM,NBG(GUJARAT)
8	HARYANA	GM,NBG(CHANDIGARH)
9	HIMACHAL PRADESH	GM,NBG(CHANDIGARH)
10	JHARKHAND	GM,NBG(JHARKHAND)
11	KARNATAKA	GM,NBG(SOUTH II )
12	KERALA	GM,NBG(SOUTH)
13	MADHYA PRADESH	GM,NBG (MP-CH)
14	MAHARASHTRA	GM,NBG(WEST-II)
15	MANIPUR	GM,NBG(EAST)
16	MEGHALAYA	GM,NBG(EAST)
17	MIZORAM	GM,NBG(EAST)
18	NAGALAND	GM,NBG(EAST)
19	ODISHA	GM,NBG(EAST)
20	PUNJAB	GM,NBG(CHANDIGARH)
21	RAJASTHAN	GM,NBG(NEW DELHI)
22	SIKKIM	GM,NBG(EAST)
23	TAMILNADU	GM,NBG(SOUTH)
24	TELENGANA	GM,NBG(SOUTH II )
25	TRIPURA	GM,NBG(EAST)
26	UTTARPRADESH	GM,NBG(CHANDIGARH)
27	UTTARAKHAND	GM,NBG(CHANDIGARH)
28	WEST BENGAL	GM,NBG(EAST)
	<b>UNION TERRITORY</b>	
1	U.T.OF ANDAMAN & NICOBAR ISLAND	GM,NBG(EAST)
2	U.T. OF CHANDIGARH	GM,NBG(CHANDIGARH)
3	U.T.OF DAMAN & DIU, DADRA-NAGAR HAVELI	GM,NBG(GUJARAT)
4	U.T.OF LAKSHWADEEP	GM,NBG(EAST)
5	U.T.OF PUDUCHERRY	GM,NBG(SOUTH)
6	DADRA & NAGAR HAVELI	GM,NBG(GUJARAT)
7	NEW DELHI	GM,NBG(NEW DELHI)
8	JAMMU & KASHMIR	GM,NBG(CHANDIGARH)



## Loan Application Form For Star Sakhi Scheme (SSS)

The Branch Manager,

\_\_\_\_\_ Branch

PHOTOGRAPH
------------

Dear Sir,

I \_\_\_\_\_, Belong to SHG group \_\_\_\_\_  
 hereby apply for Cash Credit/Term Loan/Demand Loan of Rs. \_\_\_\_\_ (Rupees  
 \_\_\_\_\_ only) & furnish below the necessary information.

Name of the Enterprise										
Constitution										
Current Business Address	State		PIN Code							
	Business Premises		√	Rented		Owned				
Telephone No.		Mobile No.	91							
E-mail:										
Business Activity	Existing									
	Proposed									
Date of Commencement(DD/MM/YYYY)										
Whether the Unit is Registered	√	Yes		No						
If Registered (Please mention: Registration no. And the Act under which registered )										
Registered office Address										
Social Category	√	SC	ST	OBC	Minority Community					
If Minority Community	√	Buddhists	Muslims	Christians	Sikhs	Jains	Zoroastrians			

## Background Information of Individual:

S.No	Name	Date of Birth	Sex	Residential Address with Mobile No.	Academic Qualification	Experience in the line of activity (Years)
1.						

S.No	Id proof	Id proof no.	Address proof	Address proof no.	PAN Card/DIN No.	Relationship with the officials/ Director of the bank if any





**Banking/Credit Facilities Existing:****(In Rs.)**

Type of Facilities	Presently Banking with	Limit Availed	Outstanding As on .....	Security lodged	Asset classification status
Savings Account		N. A.		N. A.	
Current Account		N. A.		N. A.	
Cash Credit					
Term Loan					
LC/BG					
If banking with this bank, customer ID to be given here:					
It is certified that our unit has not availed any loan from any other Bank / Financial Institution in the past and I/we am/are not indebted to any other Bank / Financial Institution other than those mentioned in column no. E above.					

**Credit Facilities Proposed :****( In Rs.)**

Type of Facilities	Amount	Purpose for which Required	Details of Primary Security Offered (with approx. value to be mentioned)
Cash Credit			
Term Loan			
LC/BG			
Total			

**In case of Working Capital: Basis of Cash Credit Limit applied :****(In Rs.)**

Actual Sales		Projected						
FY-	FY-	Sales	Working Cycle in Months	Inventory	Debtors	Creditors	Promoter's Contribution	Limits

**In case of Term loan requirements, the details of machinery/equipment may be given as under:**

Type of machine/ Equipment	Purpose for which required	Name of Supplier	Total Cost of Machine	Contribution being made by the promoters (Rs.)	Loan Required (Rs.)
<b>Total</b>					

Repayment period with Moratorium period requested for	
---	--



**Past Performance / Future Estimates:****(In Rs.)**

Past Performance / Future Estimates (Actual performance for two previous years, estimates for current year and projections for next year to be provided for working capital facilities. However for term loan facilities projections to be provided till the proposed year of repayment of loan)				
	Past Year-II (Actual)	Past Year-I (Actual)	Present Year (Estimate)	Next Year (Projection)
Net Sales				
Net Profit				
Capital (Net Worth in case of Companies)				

**Status Regarding Statutory Obligations:**

Statutory Obligations	Whether Complied with (select Yes/No) If not applicable then select N. A.	Remarks (Any details in connection with the relevant obligation to be given )
1. Registration under Shops and Establishment Act		
2. Registration under MSME (Provisional/ Final)		
3. Drug License		
4. Latest Sales Tax Return Filed		
5. Latest Income Tax Returns Filed		
6. Any other Statutory dues remaining outstanding		

**Declaration:**

I / We hereby declare that the particulars given above are true and correct to the best of my/our knowledge and belief.

I/ We hereby authorise the Bank to disclose all or any particulars or details or information relating to my/our loan accounts with the Bank to any other financial institution, government or any agency(ies) as may be considered necessary or desirable by the Bank.

It will be in order for the Bank to disqualify me/us from receiving any credit facilities from the Bank In case it is proved that the declaration of my/our outside borrowings made above contain misrepresentation of facts.

I/ We hereby declare that I /We have no borrowings /liabilities excepting those mentioned under Item (6) as on the date of application.

I/We hereby undertake to abide by the terms and conditions that the bank may stipulate in sanction of this loan and inform Bank in the event of acquiring any other assets during the tenure of the advance. You may take appropriate safeguards/action for recovery of bank's dues.



Applicant's Name

Signature(s) / Thumb Impression

Place:

Date:

**CHECK LIST: (The check list is only indicative and not exhaustive and depending upon the local requirements at different places addition could be made as per necessity)**

- 1) Proof of identity - Self certified copy of Voter's ID card / Driving License / PAN Card / Aadhar Card/Passport.
- 2) Proof of Residence - Recent telephone bill, electricity bill, property tax receipt (not older than 2 months), Voter's ID card, Aadhar Card & Passport of Proprietor/ Partners/ Directors.
- 3) Proof of Identity/Address of the Business Enterprise -Copies of relevant licenses/ registration certificates/other documents pertaining to the ownership, identity and address of business unit.
- 4) Applicant should not be defaulter in any Bank/Financial institution.
- 5) Statement of accounts (for the last six months), from the existing banker, if any.
- 6) Projected balance sheets for one year in case of working capital limits and for the period of the loan in case of term loan (Applicable for all cases from Rs.2 Lakh and above).
- 7) Project report (for the proposed project) containing details of technical & economic viability.
- 8) Photos





**BANK OF INDIA**

.....Branch

**Proposal Format for Star Sakhi Scheme (SSS)**

Branch Proposal No. -----

Date-----

Branch-----

Zone-----

**A. Borrower Details:**

1	Name of Borrower	
2.	Category (SC/ST/OBC/Other)	
3.	Age	
4.	Academic Qualification	
5.	Worth	
6.	Activity	
7.	Name of Principal Person	
8.	Name of Co applicant, if any	
9.	Constitution of Co applicant, if any	
10.	Scheme/BSR Code	
11	Saving Account No	
12.	Category (Agri /MSME)	
13.	Present request	

**B. SHG Details:**

1	Name of SHG	
2	SB Account No and Open date	
3	Address of SHG group	
4	Turnover in account	Satisfactory/Non- Satisfactory
4	Credit facility Availed	YES/NO
5	If yes, A/c Number and Sanction Date	
6	Credit History	Satisfactory/Non- Satisfactory

**C. Facilities & Security**

(Rs. in lakhs)

Fund based Limits	Limits		Security in brief	Value of Security	Margin %	Rate of Interest	Repayment
	Existing	Proposed					



**D. Financial Position:**

(Rs. in lakhs)

	Provisional	Estimated		Provisional	Estimated
Net Worth			Current Ratio		
Sales			Debt Equity Ratio		
Agri. Income			ISCR		
Net Profit					

**E. Assessment/Justification For Term loan/ Demand Loan/ Cash Credit:****F. Due Diligence:**

Sr No.	Description	Remarks
1	Date of Pre-Inspection	
2.	Inspection Officer	
3.	Observations & recommendations of inspection	
4.	Verification of Business / Residential Address	
5.	Verification of Certificates / Income Tax & other related documents	
6.	Reports from Existing Banker obtained on	
7.	Assets & Liabilities Statements verified	
8	Market Enquiries	
9.	CIBIL / RBI wilful defaulters' list	

**G. Security Documents:**

**H. Third party guarantee:** As per HOBC 110/89 dated 09.08.2016, all eligible activity would be covered under the guarantee cover of NCGTC under 'Credit Guarantee Fund for Micro Units'. [No collateral security/third party guarantee to be obtained]. So we have not proposed third party guarantee.

**I. Recommendation:**

Signature of  
Recommending Authority

Signature of  
Sanctioning Authority

